'Official-Legislator' Relationship

176. Dr. Karni Singh:
Shri R. S. Vidyarthi:
Shri Yashpal Singh:
Shri S. C. Samanta:
Shri Ram Kishan Gupta:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether a draft code has been prepared to regulate 'official-legislator' relationship;

(b) if so, its salient features and the reaction of State Governments;

(c) when it will be officially published and brought into force; and

(d) the built-in checks to restrain erring officials or legislators and in what manner?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) to (d). A draft Code to regulate the relationship between Members of Parliament and of State Legislature and the Administration has been prepared. A copy of the draft Code was laid on the Table of the Lok Sabha on 21st March, 1967. It is proposed to finalise the code after it has been discussed in a meeting of the representatives of the various political parties and groups in Parliament, and after the State Governments have been consulted.

'चिनलैण्ड' आन्दोलन

177. श्री मोहन स्वरूप :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री क० म० सिंह देव :
श्री श्रीधरन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के 'चिन' निवासियों ने "चिनलैण्ड" के निर्माण के लिए आन्दोलन आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि मनीपुर में प्रचार के लिए बड़े पैमाने पर "पैम्फलेट" बांटे जा रहे हैं जिनमें चिनलैण्ड का नक्शा दिखाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). यह प्रश्न कुछ लोगों द्वारा 1958 में उठाया गया था और कुछ पर्चे भी बांटे गये थे । इस समय इस तरह की कोई हलचल नहीं है ।

(ग) इस बारे में सरकार की पूर्ण असहमति है ।

राजनैतिक बन्दियों की रिहाई

178. श्री मोहन स्वरूप : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर के मुख्य मन्त्री ने घोषणा की है कि काश्मीर में सभी राजनैतिक बन्दी तथा नजरबन्द व्यक्ति शीघ्र ही रिहा कर दिये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). जम्मू व काश्मीर के मुख्य मन्त्री ने कहा है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को उतनी अवधि से अधिक समय तक नजरबन्द नहीं रखना चाहती जितनी अवधि तक उसको नजरबन्द रखना जरूरी होता है । तदनुसार समय-समय पर किए जाने वाले स्थिति के पुनरवलोकन के बाद बहुत से नजरबन्दों को रिहा किया जा रहा है । इस बारे में भारत सरकार की नीति भी वही है जो राज्य सरकार की है ।